सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 21 OCTOBER TO 27 OCTOBER 2020 • VOLUME- 13 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

*T&C apply

कांग्रेस-राजद पर राजनाथ का तंज, कहा- लालटेन फूट गई है और तेल बह गई, अब न पंजा के चली और न.....

■ कहलगांव (भागलपुर)/ब्यूरो

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोडी की तरह ही भाजपा-जदयू का गठबंधन है तथा इस बात पर तो बहस की जा सकती है कि बिहार में गठबंधन सरकार द्वारा कितना विकास किया गया किंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं उठा सकता। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक चुनावी रैली में राजनाथ ने प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि लोगों ने इसके 15 साल के कार्यकाल को देखा है तथा उसके कुशासन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के ''सुशासन'' के बीच के अंतर को देखा जा सकता है। राजनाथ ने 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए

कहा, भाजपा और जदयू का गठबंधन भारतीय क्रिकेट टीम के सचिन और सहवाग की शुरुआती जोड़ी के रूप में सुपरहिट है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने बिजली, सड़क और पानी की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसकी बिहार में दशकों से कमी थी। राजनाथ ने कहा, लोगों ने लालटेन (राजद के चुनाव चिन्ह लालटेन) के 15 साल के शासन को देखा है और उन्होंने भाजपा-जदयू गठबंधन सरकार के दौरान बिहार के विकास को भी देखा है। इन दोनों सरकारों के प्रदर्शन की तुलना नहीं की जा सकती है। राज्य राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान बदल गया। राजद और कांग्रेस पर राजनाथ ने भोजपुरी में ही तंज कसा तो सभा तालियों से गूंज उठी। राजनाथ सिंह ने कहा कि यहां लालटेन फूट गई है, तेल बह गई। अब ना पंजा का चली ना उनकर कोई खेल चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सुशील मोदी की प्रशंसा करते हुए राजनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं। उन्होंने ने कहा, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए सब कुछ किया है। इस पर बहस हो सकती है कि क्या उन्होंने पर्याप्त काम किया है या कम काम किया है या अधिक किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई बहस नहीं हो सकती है। राजनाथ ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर उंगली नहीं उठा सकता। राजनाथ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने न केवल गरीबों और दलितों को सशक्त बनाया बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक गतिरोध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का उल्लेख करते हुए राजनाथ ने कहा कि वह उनकी बहादुरी के लिए राज्य के लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा, आप सभी जानते हैं कि गलवान घाटी में क्या हुआ था। यह बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे जिन्होंने हमारी मातृभूमि के गौरव को बचाया। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और मै उनके बलिदान के लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूं। बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए तीन चरणों 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और सात नवंबर को मतदान होना है और मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। भाजपा-जदयू गठबंधन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर तथा बालीवुड के सेट डिजाइनर से राजनेता बने मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरा है। उनके मुकाबले में विपक्षी महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और अन्य वामदल शामिल हैं। कुछ अन्य छोटे दल भी चुनाव मैदान में हैं।

महंगाई लूट रही बचत और जेब की कमाई, बाज़ार में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बाजार में महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डाला दिया है. सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में हो रही बेमौसम बारिश के चलते आलू-प्याज और टमाटर के दामों में भारी उछाल आ गया है। बाजारों में टमाटर 70 से 80 रुपये प्रति किलो और आलू 45 से 55 रुपये प्रति किलो बिक रह है. प्याज़ 60-70 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। प्याज पिछले साल की तरह उपभोक्ताओं के आंसू निकाल रहा है. बरसात में फसल खराब होने की वजह से प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं। प्याजा बाजार में 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. चेन्नई के खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें मंगलवार को 73 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई. मंगलवार को दिल्ली में प्याज का खुदरा भाव 51 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 65 रुपये प्रति किलोग्राम और मुंबई में 67 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। गौरतलब है कि नवरात्र में उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्से में लोग लहसुन-प्याज नहीं खाते हैं, जिससे खपत कम होती है, मगर इससे प्याज की महंगाई से राहत नहीं मिली। कारोबारी बताते हैं कि, साउथ और महाराष्ट्र में बारिश हुई, यानी प्याज उत्पादक राज्यों में बारिश के कारण फसल खराब हो गई, जिसके कारण शॉर्टेज है। वहीं नई फसल आने में

देर है, जहां कहीं भी नई फसल आ रही है, वो भी पर्याप्त नहीं है. साथ ही ऊंचे भाव पर ही किसान के पास से आ रहा है प्याज।

फेस्टिव सीजन में महंगाई की मार लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. पहले ही कोरोना संकट ने लोगों की आर्थिक स्थिति को खासा प्रभावित किया है अब सब्जियों के दाम बढ़ जाने लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ी रही है।

मेरा जालंधर दिल दे अंदर परन्तु यहाँ स्वच्छता अकेली कागजों के अंदर

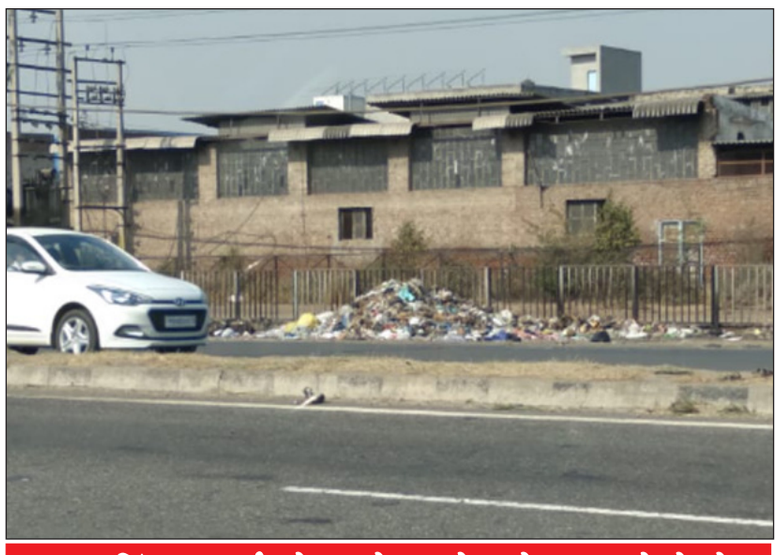

लम्मा पिंड फ्लाई ओवर से पहले लगे हुए कूड़े के ढेर

बल्टर्न पार्क के बाहर डेविएट इंजीनियरिंग कालेज बोर्ड के नीचे लगे हुए कूड़े के ढेर

जालंधर बस स्टैंड से बीएमसी चौक में बने सुलभ शौचालय के पास लगे हुए कूड़े के ढेर

पुडा दफ्तर के नजदीक गली में लगे हुए कूड़े के ढेर

120 फुटी रोड़ नजदीक भयैया मंडी चौक के पास लगे हुए कूड़े के ढेर

एच.एम.वी. कालेज के सामने दानामंडी रोड़ पर लगे हुए कूड़े के ढेर

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

स्वच्छ भारत मिशन जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया तो लोगों में उम्मीद जागी थी की अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वच्छता के मामले में छवि सुधरेगी और भारत के लोगों ने इसको भी सराहा। परन्तु भ्रष्ट अफसरों ने इस योजना के तहत करोड़ों रुपया के इश्तिहार,प्रमोशनल प्रोग्राम में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना लिया और हज़ारों सफाई

ग्राऊंड जीरो पर हालात कुछ और ही बयान कर रहे है और अफसरों की मनमानियों का पार्षदों ने कई बार हाऊस में विरोध भी दर्ज करवया

सेवकों की नौकरियों को भी छीनने का काम किया जिस पैसे से भ्रष्ट अफसर इस योजना के नाम पर पैसे की बर्बादी कर रहे है अगर उस पैसे से और सफाई सेवकों की भर्ती की जाये तो शहर को शीशे की तरह चमका देंगे परन्तु नगर निगम के उच्चाधिकारी इतने भ्रष्ट और अपने नाम को चमकाने के चक्र में इस योजना की धज्जियां उड़ा रहे और स्वच्छता सर्वक्षण 2021 में रैंकिंग सुधारने के लिए जो प्रयास किये जा रहे है वो बरसाती मेंढकों के सामान है और ग्राउंड जीरो पर हालात कुछ और ही बयान कर रहे है और अफसरों की मनमानियों का पार्षदों ने कई बार हाउस में विरोध भी दर्ज करवया और साईकल रैली में उनको ना बुलाया जाना पर अपने आप को अपमानित महसूस किया क्यूंकि बगैर पार्षद और यूनियन नेताओं के ऐसी योजनाएं सफल बनाना नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों के बस की बात नहीं।

दखल

नीतियों में उलझा किसानों का विकास

केंद्र और राज्य सरकारें कृषि को घाटे वाला क्षेत्र कह कर उसे उबारने की बात तो करती हैं, लेकिन कृषि घाटे में क्यों बनी रहती है? किसानों की माली हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? किसानों की दी जाने वाली सुविधाएं क्या किसानों के लिए मुफीद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकारें जब तक कृषि के प्रति सकारात्मक और व्यावहारिक नीति नहीं बनातीं, तब तक, कृषि और कृषक को डूबने से बचाया नहीं जा सकता।

इस साल रबी की लाखों एकड़ फसल बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हो गई। मार्च में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में घनघोर आंधी-तूफान और ओले पड़े। इससे गेंहू, जौ, सरसों, अलसी, अरहर, मटर, आलू और सब्जियों की लाखों एकड़ जमीन में लहलहातीं फसलें जमीन पर लोटने या पानी में डूब कर सड़ने लगीं। सितंबर में भी यही हाल रहा। मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों ममें बाढ़ के हालात बन गए और किसान के हाथ बर्बादी आई। फसलों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा। कुदरत किसानों पर आए दिन कहर ढाती रहती है। सरकारें राहत देकर मरहम की कोशिश करती हैं। यह एक रिवाज की तरह आजादी के बाद से निभाया जा रहा है। इससे किसानों को फौरी तौर पर कुछ राहत तो मिल जाती है, लेकिन उनकी मूल समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। आजादी के बाद से अब तक ऐसी सरकार नहीं आई, जिसने खेती-किसानी को सबसे कठिन और अनिश्चित धंधे से निकाल कर सरल और निश्चित आय का बनाने के लिए ठोस कदम उठाया हो। सरकारों की नीतियों में किसानों को लालीपॉप थमाने के अलावा कोई ठोस नीति या योजना नहीं रही। इसलिए समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं।

भारत सहित दुनिया के सभी देशों की नीतियां खेती-किसानी के प्रति नकारात्मक रही हैं। मौजूदा विकास का मॉडल सुख-सुविधाओं से संपन्न शहर पर आधारित है। गांवों को विकसित करके उन्हें पूर्ण सक्षम बनाने की योजना, भारतीय कृषि नीति का हिस्सा कभी नहीं रही। गौरतलब है कि आजादी के पहले भारत का किसान गांव छोड़ कर शहरों की ओर पलायन करने की कभी नहीं सोचता था। कुदरत की मार और विदेशी शासन की किसान-विरोधी नीतियों के कारण भी किसान अपना पुस्तैनी गांव और एकमात्र परिवार का सहारा खेती छोड़ने के लिए नहीं सोचता था। ऐसा क्या हो गया कि आजादी के बाद किसान धीरे-धीरे अपना पुस्तैनी काम-धंधा छोड़ शहर-कस्बों की ओर रुख करने लगा? शायद केंद्र और राज्य सराकारों ने कभी इस बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं।

विकसित देशों में कृषि वहां की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग नहीं है, इसलिए वहां कृषि और किसानी उनकी योजनाओं में कोई खास महत्व नहीं रखते। इसके बावजूद विकसित देशों के किसानों को वहां की सरकारें जो सुविधाएं, राहत, छूट और मदद देती हैं, उससे वहां का किसान अमन-चैन और सम्मान की जिंदगी जीता है। इसलिए कुदरत का कहर या अन्य समस्याओं की वजह से वहां का किसान आत्महत्या नहीं करता और न ही अनिश्चिय के भंवर में डूबता-उतराता है। पर वैश्विक स्तर पर कृषि की जो नीतियां चल रही हैं, वे किसानों के लिए किसी भी तरह फायदेमंद और राहत देने वाली नहीं हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार कह रही है कि उसकी नीति पिछली सरकारों से बेहतर और किसानों को खुशहाली देने वाली है। अगर ऐसा है, तो गांव छोड़ कर अच्छी सुख-सुविधाओं और बेहतर आमदनी की आस में शहर आए लोग अपने गांव लौट क्यों नहीं रहे हैं? जबकि पिछले 72 वर्षों में खाद्यान्न उत्पाद बढ़ा है और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विविधता लाने के मकसद से फसल की किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इससे जहां फसलों में पोषण की मात्रा बढ़ी, वहीं उनमें जलवायु परिवर्तन का सामना करने की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर, मोनसेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बुला कर भारतीय कृषि और किसानों को बर्बाद करने के कदम विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत उठाए गए।

मोनसेंटो के बीज परंपरागत बीजों से अधिक पैदावार तो देते हैं, पर वे अगली बार बोने के लिए बेहतर नहीं होते और उससे जमीन के बंजर होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इससे किसान दोहरी मार का शिकार हुआ। एक तो वह मोनसेंटो के बीज बोकर अपने खेतों की उर्वरा-शक्ति गंवा बैठा, वहीं परंपरागत बीजों के अनुकूल उसकी जमीन नहीं रह गई। बिजली, पानी, खाद, उत्पाद का उचित दाम न मिलने, बिचौलियों के जरिए ठगे जाने और मंहगाई की मार जैसी समस्याएं किसानों को खेती छोड़ कर शहर की ओर पलायन करने पर मजबूर करती रही हैं। वैश्विक स्तर पर विकास का मॉडल ही किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर करता है। गौरतलब है कि विकास के वैश्विक मॉडल को ही पिछले 72 सालों से सरकारें अपनाई हुई हैं। यह मॉडल किसानों को खेती से बेदखल कर उन्हें शहरों के लिए दिहाड़ी मजदूर बनाने वाला है।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते थे कि देश प्रगति के रास्ते पर तब तेजी से बढ़ेगा जब 2022 तक कम से कम 38 प्रतिशत किसानों को खेती से बेदखल कर शहरों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में लाया जाए, क्योंकि शहरों में दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत है। भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश की रही है। यहां की संस्कृति, भाषा, भाव, रीति-रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं कहीं न कहीं कृषि से सीधे जुड़ते हैं। पर आजादी के बाद कृषि की जगह उद्योग-धंधों को हर तरह से प्रोत्साहित किया गया और किसानी और किसान को हर तरह से हतोत्साहित। इसी का परिणाम है कि अब लाखों की तादाद में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। नेशनल स्कीम पॉलसी कहती है कि कृषि से देश की अर्थव्यवस्था को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनसे अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिले। आमतौर पर यह बात ठीक कही जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र से आमदनी कम हो या बहुत कम हो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन गहराई से चिंतन करने से इस बात में कोई दम नजर नहीं आता।

साल 1970 में गेंहू का दाम 75 रुपए प्रति कुंतल था और 2015 में इसका दाम 1450 रुपए के आसपास था। इन 45 सालों के दौरान सरकारी नौकरी-पेशा लोगों के वेतन में 120-150 गुने की वृद्धि हुई। जबकि किसान की आमदनी में महज 19 गुने की वृद्धि हुई। सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य भत्ता चार लाख 80 हजार रुपए मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, जजों, कर्मचारियों को 21 हजार रुपए अतिरिक्त भत्ता मिलता है। लेकिन किसानों के लिए न कोई भत्ता है, न कोई योजना, जिससे वे भी बिना तनाव के जी सकें। अरबों रुपए पूंजीपतियों को बैंक दे देते हैं और न लौटाने पर उनकी न तो कुर्की होती है और न उन्हें परेशान किया जाता है। पर किसान को दस-बीस हजार के ऋण के लिए परेशान किया जाता है और उनके खेत, घरेलू सामान और मकान की कुर्की तक होती है। सवाल है कि जिसे अन्नदाता कहा जाता है, उसी के साथ ऐसा दोहरा और गैरइंसानी व्यवहार क्यों? क्या किसान ईमानदारी के साथ कठिन मेहनत करके देश को अन्न नहीं खिलाता?

सरकारें कृषि को घाटे वाला क्षेत्र कह कर उसे उबारने की बात तो करती हैं, लेकिन कृषि घाटे में क्यों बनी रहती है? किसानों की दी जाने वाली सुविधाएं क्या किसानों के लिए मुफीद हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिन पर गौर करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि घाटे वाली खेती की सबसे बड़ी वजह किसान से ताल्लुक रखने वाली नीतियां, उसके साथ दोहरा बर्ताव, उसकी उपेक्षा और खेती-किसानी को सबसे निम्न स्तर का मान कर उसके लिए कोई ठोस योजना न बनाना है। कृषि लागत और कृषि-उत्पाद के दाम में अंतर को भी समझने की जरूरत है। सरकारें जब तक सकारात्मक व व्यावहारिक नीति नहीं बनातीं, तब तक, कृषि और कृषक को डूबने से बचाया नहीं जा सकता। अगर सरकारें वाकई किसानों के प्रति चिंतित हैं तो उन्हें ऐसी नीति बनानी होगी जो अन्नदाता को फसल का वाजिब दाम दिलाने की गारंटी दे।

विचार

एससीओ से ही शांति की डगर

चीन की युद्ध की मानसिकता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का आमना-सामना होने वाला है। अगले माह एससीओ शिखर सम्मेलन होना है। हालांकि, सम्मेलन वर्चुअल होगा। उम्मीद है कि यह सम्मेलन शांति का दौर लाने में सहायक होगा।

चीन और पाक से खराब चल रहे रिश्तों के बीच प्रधानममंत्री नरेंद्र मोदी की इन दोनों देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। रूस एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से करने जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन 10 नवंबर को किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात जिनपिंग और इमरान से हो सकती है। एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए सुरक्षा व अन्य राजनीतिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखने एक महत्वपूर्ण मंच है। वहीं, मई महीने से सीमा पर जारी तनाव के बीच इस शिखर सम्मेलन में पहली बार मोदी और जिनपिंग आमने-सामने होंगे।

उधर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने इस इलाके में सैनिकों के साथ-साथ भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर लिए हैं। चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां उसकी युद्ध की मानसिकता और तैयारियों का संकेत हैं। इससे यह जाहिर होता है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को उकसा कर लड़ाई छेड़ने की फिराक में है। इस साल मई से लेकर अब तक के घटनाक्रम से भी इसकी पुष्टि होती है। मई महीने में सीमा पर घुसपैठ व मारपीट की घटनाओं की परिणति 15-16 जून की आधी रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के रूप में देखने को मिली, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख दिखाया, जिसे भारतीय सैनिकों की सजगता से नाकाम कर दिया गया था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में भारत को लेकर चीन ने जो रुख दिखाया है, उसका दोनों देशों के संबंधों बुरा असर पड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरों से उम्मीद बंधी थी कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत होगी और सीमा विवाद हल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। पहली बार चीनी राष्ट्रपति सितंबर 2014 में भारत आए थे और दूसरी बार पिछले साल अक्टूबर में। लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फिरने में साल भर भी नहीं लगा। मई से ही चीन ने लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर जिस तरह की घुसपैठ और सैन्य गतिविधियां जारी रखी हुई हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि चीन भारत का अच्छा दोस्त और पड़ोसी हो सकता है। वह बार-बार भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में सवाल यह है ऐसे तनावपूर्ण हालात में कैसे सीमा विवाद सुलझेगा और दो पड़ोसी देश कैसे शांति से रह पाएंगे?

औद्योगिक विकास का नतीजा प्रदूषण

वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जनता सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन रही है। इसका नतीजा यह होता है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया अच्छे से अच्छा कदम भी नाकाम हो जाता है। प्रदूषण की समस्या का स्थायी इलाज निकालने के लिए भारत कई दूसरे देशों से सबक ले सकता है।

दुनियाभर में वायु प्रदूषण के सबसे खराब स्तर वाले शहरों की सालाना सूची में भारत शीर्ष पर है। गाजियाबाद शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। वैश्विक वायु गुणवत्ता का यह आंकड़ा आईक्यूएआईआर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। हर साल यह रिपोर्ट तैयार होती है। 2018 की रिपोर्ट में शीर्ष तीस प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल थे। वायु प्रदूषण में दक्षिण एशिया के तीस में से 27 शहर शामिल हैं, जिनमें भारत के अलावा पाक और बांग्लादेश के शहर भी हैं। इसके उलट चीन की राजधानी बीजिंग ने पिछले साल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है। बीजिंग दुनिया के 200 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो गया है। लेकिन भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सरकारी नीतियों और प्रयासों के बावजूद हवा की गुणवत्ता पिछले पांच साल के दौरान काफी ज्यादा बिगड़ी है।

जाहिर है, प्रदूषण की समस्या कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है और वह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि भारत में बड़े शहरों से इतर छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। वैसे तो आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण का शिकार का शिकार है, लेकिन भारत के लिए यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब समस्या इतनी व्यापक और गंभीर हो चुकी है कि दुनिया के सामूहिक प्रयास के बिना इससे निजात नहीं मिल सकती। आज के समय में हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक-पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हम कैसे योगदान दें और दूसरा-खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। वायु प्रदूषण सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में वायु प्रदूषण भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक जहरीली हवा से हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी औसतन साढ़े सात साल कम हो रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत में बड़े शहरों से इतर अब छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। हवा जहरीली और प्रदूषित होने का मतलब है कि उसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी जहरीले कणों के स्तर में वृद्धि होना। हवा में पीएम-2.5 की मात्रा 60 और पीएम-10 की मात्रा 100 होने पर सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इससे ज्यादा हो तो वह बेहद नुकसानदायक हो जाती है। ऐसी गंभीर स्थिति पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकारों को दीर्घकालीन नीतियां बना कर उन पर सख्ती से अमल करना होगा। लेकिन विकसित और विकासशील देशों में विकास के नाम पर आगे निकलने की होड़ ने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और ओजोन परत के क्षरण की समस्या ने मानव के अस्तित्व के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है।

प्रदूषण को बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उसकी जीवनशैली काफी हद तक जिम्मेवार है। प्रारंभ में जब प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण से सामंजस्य बैठा कर रहते थे। लेकिन परंतु तकनीकी विकास और औद्योगीकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। वह यह भूल गया है कि इस पृथ्वी पर उसका वजूद प्रकृति एवं पर्यावरण के कारण ही है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने त्रासदीपूर्ण भविष्य को लेकर पूरी से तरह से बेखबर हैं। सवाल उठता है कि आखिर सरकारें कर क्या रही हैं? पानी प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित और हवा प्रदूषित। देश में बढ़ते प्रदूषण का मिजाज इसी तरह से बना रहा तो आने वाले दशकों में मानव के अस्तित्व को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही होने वाला है, लिहाजा भारत को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए तत्काल सार्थक और ठोस उपाय करने होंगे। जो थोड़े-बहुत प्रयास हो भी रहे हैं, वे बेअसर साबित हो रहे हैं।

वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जनता सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन रही है। इसका नतीजा यह होता है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया अच्छे से अच्छा कदम भी नाकाम हो जाता है। प्रदूषण की समस्या का स्थायी इलाज निकालने के लिए भारत कई दूसरे देशों से सबक ले सकता है। दरअसल, कई अन्य देश भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। इन देशों में प्रदूषण से निपटने के कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनसे उन्हें कुछ सफलता भी हासिल हुई है। आज वायु प्रदूषण ऐसा गंभीर मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसे आपसी सहमति और ईमानदार प्रयासों के बिना हल नहीं किया जा सकता। वायु प्रदूषण को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम सभी नागरिकों और संगठनों से लेकर निजी कंपनियों और सरकारों तक को एक साथ मिल कर प्रयास करना होगा। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम-कानूनों और दिशानिर्देशों की कोई कमी नहीं है।

समस्या यह है कि इन नियम-कानूनों को कहीं भी उतनी सख्ती से लागू नहीं किया गया, जितनी कि जरूरत थी। इस समय भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में घुलते जहर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, इसलिए समस्या बहुआयामी है। दशकों से किसी भी सरकार या प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। अब नतीजा सामने है। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ एक एकीकृत योजना बना कर उसे गंभीरता से लागू करना भी होना चाहिए। 21वीं सदी में जिस प्रकार से हम औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, उस सुख-समृद्धि ने पर्यावरण संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह खतरे की घंटी है।

इसीलिए अब यह अत्यावश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहे और जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छ वातावरण के निर्माण को शीर्ष पर रखे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम चेत नहीं रहे हैं। साल दर साल बीत जाने के बाद भी भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। वक्त कुछ करने का है न कि सोचने का। प्रदूषण को लेकर जिस तरह से समय-समय पर चिंता दिखाई जाती है, उसे जीवन में अपनाने की जरूरत है, ताकि हम इस समस्या से निपटने में किसी तरह की ढिलाई न दिखाएं।

ट्विटर

लद्दाख में चीन ने जिस तरह के हालात पैदा किए हैं, उसमें उसी को पहल करनी होगी और शांति की राह बनानी होगी। भारत ने काफी धैर्य दिखाया है।

कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ

मामला बातचीत से सुलझ सकता है, सेना से नहीं। आर्मी स्तर की बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। कूटनीतिक चैनल से बात करनी चाहिए। उसी से हल निकलेगा।

फारूक अब्दुल्ला, अध्यक्ष नेकां

सत्यार्थ

सबसे बड़ा यज्ञ

संत रामलिंगम स्वामी करुणा और प्रेम को ही भक्ति का मूल आधार बताया करते थे। एक बार उनके पास कुछ धनी व्यापारी आए। उनमें से एक ने कहा- महाराज, हम एक यज्ञ का संकल्प लेकर आए हैं और चाहते हैं कि उस यज्ञ में पहली आहुति आप ही डालें, ताकि हमारा यज्ञ सफल हो। उनकी यह बात सुन कर रामलिंगम स्वामी बोले-यह यज्ञ अवश्य होगा। कल सबेरे आप यज्ञ में होम करने हेतु बढ़िया वस्तुएं लेकर आएं। मैं कल आपको यज्ञ के माध्यम से साक्षात देव-दर्शन कराऊंगा। अगले दिन सबेरे उनके पास यज्ञ के लिए बढ़िया सामग्री, जिसमें खाद्य सामग्री भी शामिल थी, पहुंचा दी गई। स्वामीजी ने उस सारी सामग्री से हलवा, खीर, पूरी व सब्जी आदि व्यंजन तैयार करा दिए। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाके से गरीब और अभावग्रस्त लोगों को आमंत्रित किया। उन्हें एक पंक्ति में बिठाया और फिर व्यापारियों से बोले- इन सबको सम्मान और प्रेम के साथ भोजन कराओ। यह अनुभव करो कि तुम यज्ञ में सच्चे मन से आहुतियां डाल रहे हो। अपने मन में किसी भी प्रकार का राग-द्वेष मत आने दो। बस यह सोचो कि सभी अभावग्रस्त और दो वक्त की रोटी को तरसते ये लोग साक्षात देवता बनकर आहुतियां ग्रहण कर रहे हैं। व्यापारियों ने ऐसा ही किया। उन्हें वाकई असीम संतोष और अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। सभी व्यापारियों व अभावग्रस्त लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता देख रामलिंगम बोले-जब किसी भूखे व असहाय व्यक्ति को भोजन देकर उसकी भूख तृप्त की जाती है, उस समय उसके अंतःकरण से निकला कृतज्ञता का भाव ईश्वर का आशीर्वाद होता है। स्वामीजी के अनुयायियों ने आज भी अन्नदान की परंपरा को जीवित रखा है।

कर्नाटक में ताजा बारिश से बिगड़े बाढ़ के हालात

कलबुर्गी, (एजेंसी)। कर्नाटक में ताजा बारिश होने से भीमा नदी के समीप के क्षेत्र, कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगीर जिले और अन्य स्थानों पर बाढ़ के हालात बिगड़ गए है। सोनना बैराज से भीमा नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से नदी किनारे के कई गांवों में पानी भर गया हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और सेना के जवानों ने हजारों लोगों को बाढ़ के पानी से सुरक्षित निकाल कर राहत शिविरों में भेजा है। मंगलवार सुबह सोनना बैराज के 8.20 लाख में से 3.92 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कलबुर्गी को जेवरगी से जोड़ने वाले कट्टी सांगवी के पास के एक पुल से सोमवार को वाहनों की आवाजाही को रोक दी गई था। जिले भर में खोले 162 राहत केंद्रों में 28,637 लोगों ने शरण ली है।

सार्दगी (बी) में नदी तट के पास स्थित घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, कलबुर्गी तालुक के फिरोजाबाद, रसनागी, हंडानूर और जेवरगी तालुक के हरवाल गांवों के निवासियों को राहत केंद्रों में भेजा गया है। जिले के छह तालुकों में कुल 157 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और 73 गांवों के 27,378 लोगों को एनडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग की टीमों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद के सहयोगी पर की कार्रवाई

इकबाल मिर्ची से जुड़ी 22.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

मुंबई ■ एजेंसी

प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों को मंगलवार को संलग्न किया। ईडी ने मिर्ची के परिजनों से जुड़े सात अचल खातों में सात अचल संपत्तियों और शेष राशि को जब्त की है। ईडी ने मिर्ची से जुड़ी ये संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत संलग्न की हैं। इकबाल मिर्ची के परिजनों की इस प्रॉपर्टी की कीमत 22.42 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने मिर्ची के परिजनों से संबंधित जिन संपत्तियों को संलग्न किया है, उनमें मुंबई का एक होटल, दो बंगले और पंचगनी में 3.5 एकड़ की जमीन शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले माह भी इकबाल मिर्ची पर शिकंजा कसने के लिए उसकी और उसके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को संलग्न किया था। सितंबर में ईडी ने मिर्ची की संयुक्त अरब अमीरात, दुबई की संपत्तियों सहित उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 15 संपत्तियां जब्त की थीं। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत

आने वाली इन संपत्तियों की कीमत 200 करोड़ रुपए आंकी गई थी। वित्तीय जांच एजेंसी ने पहले ही लंदन, दुबई और मुंबई में 1,000 करोड़ रुपए की मिर्ची की 30 संपत्तियों की पहचान कर ली थी।

पिछले साल दिसंबर में 600 करोड़ की संपति की थी जब्त

ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ मुंबई के प्राइम स्थानों पर सीजे हाउस, साहिल बंगला, राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू में कथित अवैध लेनदेन के लिए एक आपराधिक मामला दायर किया गया था। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्तियों में वाणिज्यिक इमारतें शामिल थीं- इनमें मुंबई के तारदिओ इलाके में वर्ली और अरुण चैंबर्स में स्थित सीजे हाउस शामिल थे, जिसकी कीमत 76 करोड़ रुपए आंकी गई थी।

कौन था इकबाल मिर्ची?

मेमन इकबाल उर्फ इकबाल मिर्ची अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी माना जाता था। वह दर्जनों मामलों में एक वांछित अपराधी था। मिर्ची पर हत्या, हत्या का प्रयास, वसूली से लेकर ड्रग तस्करी जैसे मामलें दर्ज हैं। हालांकि, 1993 मुंबई सीरियल धमाकों के आरोपियों की सूची में मिर्ची का नाम नहीं था। मुंबई धमाकों के बाद वह दुबई चला गया और वहीं अपना ठिकाना बना लिया। इंटरपोल ने साल 1994 में मिर्ची के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। साल 2013 में उसकी मौत हो गई थी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020

एक बार फिर से नीतीश कुमार? महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है सत्तारूढ़ एनडीए

नई दिल्ली ■ एजेंसी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। सीएसडीएस-लोकनीति के साथ मिलकर आजतक न्यूज चैनल ने सर्वे किया है। इस ओपिनयन पोल में एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार दिखाई दे रहा है। वहीं, पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में भी महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव से एनडीए उम्मीदवार नीतीश कुमार आगे हैं।

ओपिनियन पोल के अनुसार, विधानसभा चुनाव में एनडीए को 133 से लेकर 143 सीटें मिलने का अनुमान है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 88-98 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) महज 2-6 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य दलों की बात करें तो ओपिनियन पोल में 6-10 सीटें दी गई हैं।

37 विधानसभा के 148 बूथों पर पूछी गई लोगों की राय

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस ओपिनियन पोल के दौरान 37 विधानसभा सीटों के 148 बूथों पर लोगों की राय पूछी गई है। इस दौरान, 3731 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया है। यह ओपिनियन पोल 10 से 17 अक्टूबर के बीच कराया गया है। सर्वे एजेंसी का दावा है कि सभी आयुवर्ग के लोगों से उनकी राय पूछी गई है।

प्रदेश के 31 फीसदी लोग करते हैं नीतीश कुमार को पसंद

सर्वे के दौरान जब लोगों से मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद पूछी गई तो इसमें नीतीश कुमार सबसे आगे रहे। 31 फीसदी लोग नीतीश कुमार को फिर से राज्य का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जबकि, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को 27 फीसदी लोग सीएम देखना चाहते हैं। वहीं, चिराग पासवान पांच, डिप्टी सीएम सुशील मोदी चार और लालू यादव को तीन फीसदी लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।

एनडीए के पक्ष में 38 तो महागठबंधन के पक्ष में 32 फीसदी लोग

ओपिनियन पोल के अनुसार, 38 फीसदी लोगों ने एनडीए के पक्ष में राय रखी है, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 32 फीसदी लोग हैं। इसके अलावा, छह फीसदी लोगों की चाहत है कि राज्य में अगली सरकार एलजेपी की बने।

क्या कहता है अन्य ओपिनियन पोल?

इससे पहले, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टाइम्स नाउ और सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया था। इसमें भी एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया गया था। सर्वे के मुताबिक, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती हैं। जबकि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 7 सीटें, जिसमें पांच एलजेपी को मिल सकती हैं। अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए के 160 सीटों में भाजपा के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम और वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 56 सीटें, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटें मिल सकती हैं।

पहले चरण में 952 पुरुष एवं 114 महिलाएं डटी चुनावी मैदान में

पटना, (एजेंसी)। बिहार के 16 जिलों में पहले चरण की 71 सीटों के लिए चुनाव को लेकर 952 पुरुष व 114 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कुल 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 28 अक्टूबर को होगा। कटोरिया में सबसे कम पांच प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं तो गया टाउन चुनाव क्षेत्र से सबसे अधिक 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गयी। स्क्रूटनी के बाद अब तक 1510 प्रत्याशी चुनावी स्पर्धा में है। दूसरे चरण के लिए मतदान तीन नवंबर को होना है। वहीं, तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है और मंगलवार की शाम तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस चरण के लिए अबतक 337 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वाल्मीकिनगर लोकसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी तीसरे चरण के साथ ही चुनाव निर्धारित है और अब तक 03 नामांकन पत्र दाखिल किए गए है। तीसरे चरण के लिए मतदान 07 नवंबर को होगा।

न्यूज

पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल ने बेटे के साथ छोड़ी भाजपा

जींद, (एजेंसी)। हरियाणा भाजपा के पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल ने कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। उनके बेटे तथा पार्टी के स्टेट मीडिया पेनलिस्ट रविंद्र ढुल ने भी भाजपा छोड़ दी है। रविंद ने एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) पद से भी त्याग-पत्र दे दिया है। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन नए कानूनों का विरोध करते हुए परमेंद्र व रविंद्र ढुल ने पार्टी छोड़ी है। जींद स्थित अपने आवास पर सुबह पत्रकारों से बातचीत में श्री ढुल ने कहा कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे उसे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पास ईमेल के जरिए भेज भी दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री दशई चौधरी जदयू में शामिल

पटना, (एजेंसी)। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मंगलवार को राजद विधायक नेमतुल्लाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री दशई चौधरी को जदयू की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस के सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला और शिवहर जिला प्रभारी आदित्य मिश्रा ने भी अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जदयू ने टिकट नहीं मिलने से बागी होकर मैदान में उतरे पार्टी के दो लोगों की सदस्यता निलंबित कर दी। प्रदेश जदयू अध्यक्ष सिंह ने नालंदा जिले के हरनौत से चुनाव लड़ रही ममता देवी और ई. अशोक कुमार सिंह को जदयू की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए छह साल के निष्कासित कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश के गौरव शर्मा बने न्यूजीलैंड में सांसद

वेलिंगटन, (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के हमीपुर में रहने वाले डॉ. गौरव शर्मा ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गौरव न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। हेमिल्टन वेस्ट सीट से उन्होंने 16,950 वोट हासिल किए और अपने विरोधी नेशनल पार्टी के नेता टिम मैकिन्डो को 4425 वोट से हराया। गौरव शर्मा का परिवार करीब 20 साल पहले न्यूजीलैंड जाकर बस गया था, तब वह नौवीं क्लास में थे। शुरुआत में वहां परिवार को नए माहौल में ढालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद गौरव शर्मा ने वहां से मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर डिग्री हासिल की। गौरव हैमिल्टन में प्रैक्टिस करते हैं।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार, कहा

तब 1962 में 15 मिनट में चीन को क्यों नहीं बाहर फेंक पाई कांग्रेस सरकार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनाव के बीच राहुल गांधी के 15 मिनट वाले बयान पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को 1962 में अपनी सलाह सुननी चाहिए थी, जब भारत ने चीन के साथ युद्ध के दौरान कई हेक्टेयर भूमि खो दी थी। उन्होंने कहा कि 1962 में कांग्रेस ने 15 मिनट में चीन को बाहर क्यों नहीं फेंका। दरअसल, अमित शाह ने 7 अक्टूबर को हरियाणा में नए किसान कानूनों के खिलाफ एक रैली के दौरान पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के संबंध में राहुल गांधी की 15 मिनट वाले बयान पर जवाब दिया। राहुल गांधी के बयान अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर फेंक देते पर अमित शाह ने एक टीवी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इसे 1962 में ही अप्लाई कर लेना चाहिए था। अगर वो 1962 में ही ऐसा कर लेते, तो भारत ने अपनी हेक्टेयर्स भूमि न खो दी होती। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने तो आकाशवाणी पर यह तक कह दिया था- बाय-बाय असम। कांग्रेस पार्टी हमें ये नसीहत कैसे दे सकती है। आपके परनाना की सरकार थी, तभी चीनी सरकार के हाथों हमारी जमीनें जाती रहीं।

मुझे 16 बिहार रेजीमेंट पर गर्व

15 जून को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष पर अमित शाह ने कहा कि मुझे 16 बिहार रेजीमेंट पर काफी गर्व है। हमारे समय में हमने कम से कम डटकर मुकाबला किया है। मैं गर्व करता हूं बिहार रेजीमेंट के उन जवानों पर, जिन्होंने हड्डियां गलाने वाली ठंड में भी रात को मुस्तैद रहकर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा की है और कठोर जवाब दिया है। हालांकि, अमित शाह ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने किया था दावा

दरअसल, 7 अक्टूबर को हरियाणा में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने कहा था कि किसी ने भी भारत की जमीन नहीं छीनी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज, दुनिया में केवल एक ही देश है जिसकी भूमि दूसरे देश द्वारा ली गई है और पीएम खुद को देशभक्त कहते हैं। अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर निकाल फेंकते।

जावडेकर ने बालिका दिवस को लेकर की अनंतपुर प्रशासन की पहल की प्रशंसा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला प्रशासन के पहल की प्रशंसा की, जिसके अंतर्गत जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में एक दिन के लिए एक बालिका को विभाग प्रमुख के तौर पर काम करने का मौका मिला। श्री जावडेकर ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अनंतपुर जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल की। उन्होंने कहा कि एक कृषि मज़दूर की सोलह साल की बहादुर बेटी एम. वनी ने 11 अक्टूबर को एक दिन के लिए अनंतपुर जिला कलेक्टर का दायित्व संभाला। जिला प्रशासन ने एक बालिका को एक दिन के लिए हर सरकारी दफ्तर में विभाग प्रमुख का दायित्व देने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर 'बालिका भविष्य है' नाम के कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने 11 अक्टूबर को वनी नाम की बालिका को एक दिन के लिए जिला कलेक्टर की कुर्सी पर काम करने का मौका दिया था। इसके लिए वनी का चयन लॉटरी के जरिए हुआ था।

67 साल बाद दी जाएगी महिला को मौत

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका में 67 साल बाद किसी महिला को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इस महिला को 8 दिसंबर को जानलेवा इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दिया जाएगा। अमेरिका में 1953 में आखिरी बार किसी महिला को मौत की सजा दी गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2004 में लिसा मांटगोमेरी ने इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था। लिसा पालतू कुत्ता खरीदने के बहाने 23 वर्षीय बॉबी स्टीनेट के मिसौरी स्थित घर पहुंची थी। मांटोगोमैरी ने सबसे पहले 8 महीने की गर्भवती स्टीनेट की रस्सी से गला घोंटकर जान ले ली। इसके बाद स्टीनेट का पेट फाड़ कर बच्चा लेकर फरार हो गई। पकड़े जाने पर मोंटगोमरी ने मिसौरी की कोर्ट में अपराध स्वीकार कर लिया था और फिर 2008 में जज ने उसे अपहरण व हत्या का दोषी ठहराया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान दोषी के वकीलों ने कोर्ट में उसके बीमार होने का तर्क दिया और लेकिन जज ने इसे खारिज कर दिया। गिरफ्तारी के बाद मोंटगोमरी ने मिसौरी की अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर लिया था। 2008 में जज ने उसे अपहरण व हत्या का दोषी ठहराया। मांटोगोमैरी ने इसके बाद कई संघीय अदालतों का दरवाजा खटखटाया, किंतु हर जगह उसकी सजा बरकरार रखी गई। मांटोगोमैरी अब 52 साल की है और जब उसने यह अपराध किया था तब उसकी उम्र 36 साल थी।

मुख्तार अंसारी हुआ डिप्रेशन का शिकार

यूपी पुलिस लेने गई पंजाब तो लौटा दिया खाली हाथ

रोपड़/पंजाब, (एजेंसी)। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी डिप्रेशन में चला गया है। डॉक्टरों ने उसे तीन माह बेड रेस्ट की सलाह दी है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेने यूपी पुलिस रोपड़ पहुंची थी, किंतु खाली हाथ लौट आई। उसे तीन माह तक यूपी नहीं ले जाया जा सकता।

मुख्तार पर आजमगढ़ जिले में शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ जहां मुख्तार एवं उसके सहयोगियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है तो वहीं पुराने मामलों की भी पड़ताल चल रही है। ऐसे ही एक मामले में एसपी के निर्देश पर तरवां थाना क्षेत्र में हुई हत्या में मुख्तार समेत उसके आठ सहयोगियों पर गैंगेस्टर के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मामले में गैंगेस्टर कोर्ट ने 22 को मुख्तार समेत अन्य नामजद अभियुक्तों को तलब किया है।

ये हे मामला

आजमगढ़ जिले में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में एक सड़क निर्माण का ठेका विरोधी गुट को मिल गया था। ठेकेदार जब निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचा तो उसे लक्ष्य कर फायरिंग की, इसमें ठेकेदार बच गया, किंतु दो मजदूर घायल हो गए। बाद में एक मर गया। मामले में मुख्तार समेत 12 लोग नामजद किए गए।

इंसाफ के लिए नौ दिन से भूख हड़ताल पर बैठा रेप पीड़िता का परिवार

जयपुर, (एजेंसी)। जिले एक गांव में एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसके परिजन आरोपी के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराते हैं, लेकिन घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस से परेशान पीड़ित परिवार अब न्याय के लिए भूखे पेट खेत में नौ दिनों से धरना दे रहा है।

दरअसल जोधपुर के फलौदी में स्थित चाकू थाना क्षेत्र में माता-पिता पिछले नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनके साथ दो मासूम भी हैं। इस परिवार का आरोप है कि इनके खेत में काम करने वाले एक व्यक्ति इनके बच्ची को घर में अकेली देखकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने बच्ची को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी एक दिन अपने दोस्त के साथ आया और दोनों ने लड़की से रेप किया और फरार हो गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्कूल में एक टीचर ने भी बच्ची से छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

कमला हैरिस की भतीजी के दुर्गा मां वाले ट्वीट पर मचा बवाल

हिंदू समूहों ने जताई नाराजगी, की माफी की मांग

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस की ओर से ट्वीट की गई एक तस्वीर को लेकर अमेरिका में हिंदू समुदाय के बीच नाराजगी है।

तस्वीर में कमला हैरिस को दुर्गा मां के रूप में दिखाया गया है और समुदाय ने इसके लिए मीना से माफी की मांग की है। पेशे से वकील और बाल पुस्तकों की लेखक 35 वर्षीय मीना ने अब वह ट्वीट हटा दिया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के सुहाग ए शुक्ला ने एक ट्वीट किया कि आपने मां दुर्गा की जो तस्वीर साझा की, जिसमें उनके चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाया गया है, उससे दुनियाभर में हिंदू समुदाय के अनेक लोग व्यथित हैं। हिंदू अमेरिकी समुदाय के इस प्रतिनिधि संगठन ने धर्म से संबंधित तस्वीरों के व्यवसायिक इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हिंदू अमेरिकन

पोलिटीकल एक्शन कमेटी के ऋषि भूतड़ा ने कहा कि अपमानजनक तस्वीर मीना हैरिस ने नहीं बनाई और उनके ट्वीट करने से पहले यह तस्वीर वॉट्एसप पर चल रही थी।

अपराध फिल्मी शख्सियतों से जुड़े ड्रग्स केस की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज को मिला धमकी भरा पत्र

दो अभिनेत्रियों और हिंसा के आरोपियों को जमानत देने की मांग

बेंगलुरु ■ एजेंसी

कर्नाटक में फिल्मी शख्सियतों से जुड़े ड्रग्स यानी मादक पदार्थ के एक मामले में सुनवाई कर रहे एक एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश को सोमवार को धमकी भरा खत और डेटोनेटर के साथ एक पार्सल मिला, जिसमें उनसे दो फिल्मी अभिनेत्रियों और बेंगलुरु में 11 अगस्त को हिंसा के मामले के कुछ आरोपियों को जमानत देने की मांग की गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के

शीर्षस्थ सूत्रों के अनुसार तुमकुरु जिला मुख्यालय से भेजा गया एक पार्सल और ड्रग मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र अदालत के बाहर मिला है। इस मामले में फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी समेत कुछ बड़े लोगों के नाम आरोपी के तौर पर आये हैं। सूत्रों ने बताया कि जब अदालत कर्मियों ने पत्र को खोला तो उन्हें संदिग्ध वस्तु नजर आई और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने पुष्टि की कि इसमें डेटोनेटर है।

कर्नाटक में ड्रग्स का बड़ा रैकेट आया सामने

बता दें कि कर्नाटक में ड्रग्स का बड़ा रैकेट सामने आया है। इससे पहले सोमवार को राजस्व खुफिया निदेशालय ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से हाल ही में 13.2 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13 करोड़ रुपए से अधिक है। डीआरआई बेंगलुरु के अनुसार, फोटो एलबम, फोटो फ्रेम, चूड़ियों और निजी उपयोग की अन्य वस्तुओं में छुपाकर इस मादक पदार्थ को कुरियर के जरिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे भेजा गया था।

फोटो एलबम में छुपा कर रखा था मादक पदार्थ

निदेशालय ने कहा कि यह पार्सल चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया जाना था। यह सिंगापुर तक पहुंच भी गया था, लेकिन कुछ सूचना मिलने से इसे वापस मंगवाया गया। जांच के दौरान यह बात सामने आयी कि मादक पदार्थ को फोटो एलबम और फोटो फ्रेम में छुपा कर रखा गया था। निदेशालय ने कहा कि इस मादक पदार्थ का उपयोग मेटाम्फेटामाइन जैसे नशीले पदार्थों के निर्माण में होता है।

ड्रैगन की नाक में दम करने वाले इस देश से शुरू होगी ट्रेड वार्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत लद्दाख सीमा विवाद के बाद बढ़े तनाव के बीच चीन को पटखनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में अब भारत चीन के दुश्मन देशों के साथ बातचीत शुरू करने जा रहा है। दरअसल, चीन की हरकतों से भारत और ताइवान दोनों परेशान हैं। इससे दोनों देशों में करीबी बढ़ रही है और वे ट्रेड डील पर औपचारिक बातचीत शुरू करने वाले हैं। ताइवान कई साल से ट्रेड डील पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत इससे कतराता रहा है। दरअसल, भारत लद्दाख सीमा विवाद से पहले तक चीन की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। अब कुछ महीनों से सरकार में ताइवान के साथ ट्रेड डील के पक्ष वाला धड़ा हावी हो रहा है।

एक अधिकारी ने बताया कि ताइवान के साथ ट्रेड डील से भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अभी यह साफ नहीं है कि बातचीत कब शुरू होगी। इसी माह भारत ने स्मार्टफोन बनाने के लिए कई कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक द्वारा किसानों का दंडित ब्याज माफ करने का फैसला: रंधावा

69000 कर्जदार किसानों को 61.49 करोड़ रुपए के दंडित ब्याज से मिलेगी राहत

• चंडीगढ़/ब्यूरो

कोविड-19 महामारी और पंजाब के किसानों की वित्तीय हालत को ध्यान में रखते हुए पंजाब रा%य सहकारी कृषि विकास बैंक (पी.ए.डी.बी) द्वारा खरीफ 2020 की वसूली मुहिम के दौरान किसानों का दंडित ब्याज माफ करने का फ़ैसला किया गया है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा दी। स. रंधावा ने कहा कि पी.ए.डी.बी. के जो डिफॉल्टर कर्ज़दार 31 दिसंबर 2020 तक अपनी पूरी डिफॉल्टर राशि जमा करवाएंगे या खाता बंद करेंगे, उनके कर्ज़ खाते में खड़ा पूरा दंडित ब्याज माफ कर दिया जायेगा। राज्य में कुल 89 पी.ए.डी.बीज़ के लगभग 69000 डिफॉल्टर कर्ज़दार हैं जिनकी तरफ लगभग 1950 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर राशि बकाया है और 61.49 करोड़ रुपए का दंडित ब्याज लेने योग्य है।

इनमें से 70 प्रतिशत तो ज़्यादा छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम ज़मीन है।

इस फैसले से उनको बकाया रकम भरने में राहत मिलेगी। सहकारिता मंत्री के आदेशों पर इस सम्बन्धी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स द्वारा सिफारिश करने के उपरांत रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं, पंजाब द्वारा मंजूरी दे दी गई है। स. रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। कर्ज माफी स्कीम के अंतर्गत अब तक साढ़े पाँच लाख से अधिक किसानों का 4500 करोड़ रुपए के करीब कर्ज माफ किया जा चुका है। हाल ही में केंद्र की तरफ से बनाए गए काले कृषि कानूनों को प्रभावहीन बनाने के लिए कल ही विधानसभा में नये कानून बनाए गए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

नई एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने पर एस.सी./बी.सी. मंत्रियों और विधायकों ने किया मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद

• चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणियों से सम्बन्धित कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने पंजाब के एस.सी. विद्यार्थियों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एस.सी. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद किया है।

आज पंजाब विधानसभा में एक विशेष मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि इस स्कीम के साथ जरूरतमंद और ग़रीब परिवारों के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा।

उन्होंने इस लोक हितैषी फैसले के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद करते हुए इसको राज्य के ग़रीब परिवारों के लिए एक वरदान बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एस.सी. स्कॉलरशिप स्कीम को चालू रखने से अपने हाथ पीछे खींचकर हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अपने स्तर पर शुरू की गई इस नयी स्कीम से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सरकारी और प्राईवेट संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की निजी वचनबद्धता बारे बताते हुए मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत आय के मापदण्डों को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस स्कीम में शामिल करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अकादमिक सैशन 2020-21 से शुरू होने वाली यह योजना पंजाब के निवासी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, अरुणा चौधरी, चरनजीत सिंह चन्नी, रज़िया सुलताना के अलावा डिप्टी स्पीकर अजायब सिंह भट्टी, विधायक राज कुमार वेरका, सत्कार कौर, बलविन्दर सिंह लाडी, बलविन्दर सिंह धालीवाल, राज कुमार चब्बेवाल, हरजोत कमल, सुरिन्दर सिंह, दविन्दर सिंह घुबाया, नत्थू राम, प्रीतम सिंह कोटभाई, कुलदीप सिंह वैद्य, तरसेम सिंह डी.सी., सुशील कुमार रिंकू और निर्मल सिंह शुतराना आदि उपस्थित थे।

आबकारी विभाग द्वारा पंजाब पुलिस के सहयोग से अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए ऑपरेशन रैड रोज़ की शुरूआत

गाँव हाबीब-के के नज़दीक छापेमारी के दौरान 40,000 लीटर लाहन बरामद और मौके पर की नष्ट

• चंडीगढ़/ब्यूरो

अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसते हुए आबकारी विभाग द्वारा ऑपरेशन रैड रोज़ की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग और आबकारी अधिकारियों की टीमों ने आबकारी से सम्बन्धित ऐसे सभी जुर्मों के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए आपसी सहयोग के साथ काम कर रही हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब में अवैध शराब, शराब की तस्करी, अवैध शराब के व्यापार को रोकने के लिए ठोस यत्न किये जा रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि फिरोज़पुर ज़ोन में हो रही गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने की रणनीति के हिस्से के तौर पर 20 अक्तूबर 2020 को फिरोज़पुर के गाँव हबीब-के के नज़दीक सतलुज नदी के इलाके में छापे मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि इस छापेमारी का नेतृत्व आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा साझे तौर पर की गई।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस छापेमारी के दौरान 40,000 लीटर लाहन बरामद की गई और मौके पर ही नष्ट की गई। इसके अलावा 17 तिरपालें, 5 लोहे के ड्रम और 3 एलमूनियम के बर्तन भी जब्त किये गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की तरफ से थाना सदर, फिरोज़पुर में भी इस सम्बन्धी एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि अवैध शराब पर लगाम लगाने की मुहिम भविष्य में भी जारी रहेगी और इस अवैध कारोबार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

SPORTS PLANET

'मैदान के अंदर और बाहर एकजुट। बता दें कि रोनाल्डो को बुधवार को स्वीडन के खिलाफ पुर्तगाल के नेशन्स लीग मैच से बाहर कर दिया गया है और अब वह पृथकवास में हैं।

स्पोर्ट्स प्लैनट

बांग्लादेश के तीन क्रिकेटर कोरोना वायरस पॉजिटिव, शिविर को किया गया बंद

• ढाका/ब्यूरो

बांग्लादेश की अंडर-19 राष्ट्रीय टीम के तीन क्रिकेटर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 15 अन्य में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। एक समाचार पत्र की खबर में यह दावा किया गया है। ढाका के 'द बिजनेस स्टैंडर्ड' में छपी खबर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के खेल विकास मैनेजर एईएम कवसेर के हवाले से कहा गया है कि ये सभी खिलाड़ी बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान (बीकेएसपी) में चल रहे शिविर का हिस्सा थे। इस शिविर का आयोजन जूनियर एशिया की तैयारियों के लिए किया गया था लेकिन इस टूर्नामेंट को अब स्थगित कर दिया गया है। कवसेर ने समाचार पत्र से कहा, ''हमारे नियमों के अनुसार, लक्षण दिखने वाले लोगों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को हमने पृथक किया है।'' उन्होंने कहा, ''कुछ लोगों में लक्षण दिख रहे थे इसलिए हमने कमरे में उनके साथ रहने वालों और उनके साथ नेट अभ्यास करने वालों को भी पृथक किया। हमारी मेडिकल टीम ने बताया है कि तीन लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। हम उनके नामों का खुलासा नहीं कर सकते लेकिन हमने उन्हें और उनके संपर्क में आने वालों को पृथक कर दिया है।'' पॉजिटिव नतीजों के बाद बीसीबी ने शिविर को बंद कर दिया है और अगले महीने और परीक्षण के बाद इसे दोबारा आयोजित करने की योजना बनाई है। अंडर-19 एशिया कप अगले महीने यूएई में होना था लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुए कोरोना पॉजिटिव

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ ने इस बात की जानकारी साझा की है। फेडरेशन ने वेबसाइट में इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 35 साल के जुवेंटस स्ट्राइकर बुधवार को यूईएफए नेशंस लीग में स्वीडन के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, महासंघ ने कहा कि रोनाल्डो को कोई लक्षण नहीं हैं और वह ठीक हैं लेकिन अब वो सेल्फ क्वारंटीन में रह रहे हैं। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ की ओर से कहा गया है कि टीम के सभी खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसमें रोनाल्डो जांच में पॉजिटिव पाए गए। रोनाल्डो के अलावा बाकी दूसरे सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नेगेटिव आए खिलाड़ी स्वीडन के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। रोनाल्डो रविवार को नेशन्स लीग में फ्रांस के खिलाफ गोल रहित ड्रा रहे मुकाबले और पिछले हफ्ते स्पेन के खिलाफ गोल रहित ड्रा रहे मैत्री मैच में भी खेले थे।

सोमवार को यूवेंटस के फारवर्ड ने ट्विटर पर अपनी और पुर्तगाल टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ खाना खाने की फोटो शेयर की थी। खिलाड़ी खाने की टेबल पर एक दूसरे के काफी करीब थे और रोनाल्डो आगे से सबके साथ फोटो ले रहे थे। साथ ही उन्होंने ट्वीट के साथ पुर्तगाली में लिखा था, ''मैदान के अंदर और बाहर एकजुट। बता दें कि रोनाल्डो को बुधवार को स्वीडन के खिलाफ पुर्तगाल के नेशन्स लीग मैच से बाहर कर दिया गया है और अब वह पृथकवास में हैं।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा माल गाड़ियों पर रोक हटाने के लिए किसान जत्थेबंदियों के फैसले का स्वागत

• चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसान यूनियनों द्वारा माल गाड़ीयाँ निकलने देने की इजाज़त देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसको राज्य के अर्थचारे और इसके पुनर्जीवन के हित में बताया। मुख्यमंत्री ने उनकी अपील को सकारात्मक समर्थन देने के लिए किसान यूनियनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसानों ने यह कदम उठाकर पंजाब के लोगों के प्रति अपने प्यार और संजीदगी का प्रदर्शन किया है क्योंकि इससे राज्य को कोयले की अति अपेक्षित सप्लाई मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि रेल रोको आंदोलन के कारण कोयले की कमी होने के कारण पंजाब के लोग मुकम्मल बिजली बंद होने का सामना कर रहे थे और किसान जत्थेबंदियों का फ़ैसला उनके लिए बड़ी राहत के तौर पर आया है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इस फैसले के साथ किसान जत्थेबंदियों ने यह भी यकीनी बनाया कि उद्योग को और परेशानी सहन न करनी पड़े और उद्योग फिर से पैरों पर खड़ा होगा। किसानों का रेल रोको संघर्ष उद्योग के लिए बड़े वित्तीय घाटे का कारण बना जबकि उद्योग पहले ही कोविड महामारी के कारण संकट में में घिरा हुआ था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि माल गाड़ीयों के चलने से राज्य में यूरिया की कमी की पूर्ति करने में सहायता मिलेगी जिससे किसान भाईचारे के लिए खाद की तत्काल ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि किसानों ने राज्य को निराश नहीं किया और वह भी निजी तौर पर यकीनी बनाएंगे कि उनकी सरकार कभी भी किसानों को निराश न करे। उन्होंने किसानों के जीवन और रोज़ी रोटी को बचाने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि केंद्र के काले खेती कानूनों के कारण किसानों पर गहरा संकट छाया हुआ है। हालाँकि, मुख्यमंत्री ने किसान जत्थेबंदियों को यात्री रेलों पर भी रोक हटाने की भी अपील की क्योंकि हर रोज़ ख़ासकर त्योहारों के समय के दौरान हज़ारों पंजाबी सफर करते हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष की ओर से मंत्रियों को निशाना बनाए जाने की आलोचना, रुझान को बताया शर्मनाक

• चंडीगढ़/ब्यूरो

कहा कथित एस.सी. वज़ीफा घोटाले और नूरपुर ज़मीन मामले में कोई अनियमितता नहीं पाई गई

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने विपक्ष द्वारा उनके मंत्रियों को निशाना बनाए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए इस रुझान को शर्मनाक बताया है। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने साफ़ कर दिया कि एस.सी. वज़ीफ़ा घोटाले और नूरपुर ज़मीन मामलों सम्बन्धी दोषों की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

उनके मंत्रियों और सरकार की छवि को ख़राब करने की विपक्ष की कोशिशों को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्टियाँ अनावश्यक इल्ज़ाम लगाकर घटिया स्तर की राजनीति कर रही हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही के दौरान दख़ल देकर अपनी बात कह रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एस.सी. वजीफे के मुद्दे की जांच तीन अतिरिक्त मुख्य सचिवों द्वारा की जा चुकी है जिनको फंड के वितरण में कोई अनियमितता नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष द्वारा ऐसी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर उनके मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनका कोई आधार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के विधायक पवन कुमार टीनू, विपक्ष के नेता हरपाल चीमा और लोक इन्साफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने आज सदन में यह मुद्दा उठाते हुए मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे की माँग की जिनको कि तीन आई.ए.एस. अधिकारियों की समिति द्वारा, जोकि कथित वजीफा घोटाले की जांच के लिए बनाई गई थी, क्लीन चिट दे दी गई है। नारेबाज़ी और शोरगुल के दौरान अकाली सदन के बिल्कुल बीच आ गए और स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को बताया कि जब तक उनके द्वारा स्पीकर पर जोर से चिल्लाने के लिए माफी नहीं माँगी जाती, तब तक उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। राजनैतिक लाभ लेने के लिए सदन की मर्यादा को भंग करने के विपक्ष के कुछ विधायकों द्वारा अपनाए जाते रुझान की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे व्यवहार की विधानसभा की परंपराओं पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी चिंता ज़ाहिर की।यह बताने योग्य है कि एस.सी. वजीफा घोटाले में 64 करोड़ रुपए की अनियमितताओं के इल्ज़ाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को इस सम्बन्धी गहराई से जांच करवाने के निर्देश दिए थे। खाद्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के नेतृत्व वाले तीन अफसरों के पैनल द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी गई थी।

अकालियों और आप के दोगले किरदार से हैरान हूँ - कैप्टन अमरिन्दर सिंह

• चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज तीन संशोधन बिलों के सम्बन्ध में शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी द्वारा शर्मनाक ढंग से दोगले किरदार का प्रदर्शन करने की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों राजनैतिक पक्ष विधानसभा में इन बिलों का समर्थन करने के कुछ घंटों बाद ही इनकी निंदा करने लग पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि विरोधी पक्षों के नेता विधानसभा में बिलों के हक में बोले और यहाँ तक कि रा%यपाल को मिलने के लिए भी उनके साथ गए परन्तु अब बाहर कुछ और ही बोली बोल रहे हैं। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने इन बिलों के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा जिनके हितों की सुरक्षा और रा%य के कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए यह बिल बनाए गए हैं। बीते दिन विधानसभा में बिलों का पक्ष लेने का ढकोसला करने के लिए अकाली दल और आप की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि इन पार्टियों की किसानों के भविष्य की रक्षा और राज्य की कृषि और अर्थचारे को बचाने में कोई रूचि नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते दिन सदन में बिल पास होने के बाद इन पार्टियों के नेताओं द्वारा की गई बयानबाज़ी ने किसानों के मुद्दे के प्रति इनकी ओर से गंभीर न होने का सच सामने लाया है। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और आप की लीडरशिप के बयानों पर प्रतिक्रया देते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यदि वह सोचते हैं कि मैं और मेरी सरकार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं तो फिर उन्होंने सदन में यह बात क्यों नहीं कही? उन्होंने हमारे बिलों का समर्थन करते हुए वोट क्यों दिया? इन दोनों राजनैतिक पक्षों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर बिलों को राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा दस्तख़त न करने की संभावना बारे की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए लोगों को गुमराह करने का दोष लगाया है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यदि मैने लोगों को मूर्ख ही बनाना होता तो मैं इमानदारी के साथ उनके साथ अपनी आशंकाएं साझा क्यों करता? मैं उनको झूठ परोसने की बजाय आगे आने वाली पस्थितियों बारे खुलकर बात क्यों करता जबकि अकाली और आप झूठ बालने के पहले से ही आदी हैं? अकाली दल और आप नेताओं की तरफ से मीडिया /सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के हवाले के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विरोधी पक्षों ने राज्य सरकार के किसान पक्षीय प्रयासों की अहमीयत को घटाने की कोशिश करके अपना असली रंग दिखा दिया है जबकि इन दोनों पार्टियों ने पहले सदन में बिलों के समर्थन का दिखावा किया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार के खेती कानूनों को प्रभावहीन बनाने के लिए इन कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पास करने में उनकी सरकार का साथ दिया और यहाँ तक कि रा%यपाल को कापियां सौंपने के लिए भी साथ गए और बाद में किसानी को बचाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर इनमें कोई शर्म बाकी नहीं रही। एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि अन्य राजनैतिक पार्टियाँ ख़ास तौर पर आप, जिसकी दिल्ली में सरकार है, को पंजाब जैसे कानून लाने चाहिएं ताकि केंद्रीय खेती कानूनों के घातक प्रभावों को प्रभावहीन बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार उनकी सरकार बर्ख़ास्त कर देती है तो उनको इसकी कोई परवाह नहीं परन्तु वह आखिरी दम तक किसानों के हकों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सोचता है कि मैने कुछ गलत किया है तो वह मुझे बर्खास्त कर सकते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं पहले भी दो बार इस्तीफा के चुका हूँ और दोबारा भी दे सकता हूँ। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी तौर पर बहुत से रास्ते मौजूद हैं परन्तु उनको उम्मीद है कि राज्यपाल लोगों की आवाज़ सुनते हुए अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पंजाब की आवाज़ राज्यपाल के पास पहुँच चुकी है और वह भारत के राष्ट्रपति को बिल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति राज्य के लोगों की भावनाओं और अपील को दरकिनार नहीं कर सकते। इससे पहले आज सदन में मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर मजीठिया के बयानों वाले अखबारों की कापियां लहराईं और चुटकी लेते हुए कहा कि ये लोग सदन में कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और। उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि इस तरह का रवैया अपनाने से लोग राजनीतिज्ञों की इमानदारी पर संदेह प्रकट करना शुरू कर देंगे। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह खुश हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बीते दिन सदन में आए और खेती बिलों पर अच्छी बहस की।

• सदन में बिलों का समर्थन करने के बाद आलोचना करने पर दोनों पक्षों को आड़े हाथों लिया • केजरीवाल को किसानी बचाने के लिए ऐसे बिल लाकर पंजाब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए कहा • सिद्धू के सदन में आने और खेती बिलों पर अच्छी बहस करने से खुश हूँ

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.